जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का संवर्धन

*107. **श्रीमती माया सिंह :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल के अपने कश्मीर दौरे में राज्य में पर्यटन उद्योग में सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त पैकेज को कार्यन्वित करने की योजना की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है, और

(घ) वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान राज्य में कितने पर्यटक आये और क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि पैकेज को कार्यन्वित करने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है?

पर्यटन एंव संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां । प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान आगामी दो वर्षो में स्वतः रोजगार के अवसरो सहित कम से कम एक लाख रोजगार सृजित करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की थी।

(ख) और (ग) इस घोषणा पर आधारित, पर्यटन के पुनर्जीवन के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है (कश्मीर घाटी के लिए) । इस पैकेज के निम्नलिखित घटक हैं :-

1. हाउस बोट मालिकों के लिए सहायता
   इस योजना में बैंक द्वारा उनको उदार दरों पर ऋण प्रदान करने का प्रावधान है और पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा इमदाद प्रदान करने का भी प्रावधान है ताकि हाउस बोट मालिक 4% की ब्याज दर से ऋण ले सकें।
2. होटलों और गेस्ट हाउसों के लिए सहायता
   इस योजना में पांच सितारा होटलों को छोडकर ए,बी, सी और डी श्रेणी (राज्य सरकार की प्रमाणन शर्तो के अनुसार) में वर्गीकृत पंजीकृत होटलों/गेस्ट हाउसों के लिए बैंको द्वारा उनकी उदार दरों पर ऋण प्रदान करने का प्रावधान है । पर्यटन विभाग, भारत सरकार इमदाद प्रदान करेंगी ताकि होटल मालिक/गेस्ट हाउस मालिक 4% की ब्याज दर पर ऋण ले सकें ।
3. शिकारा मालिकों के लिए सहायता

सभी पंजीकृत शिकारा मालिक अपने शिकाराओं की मरम्मत और उन्नयन के लिए 20,000 रूपए के पूंजी अनुदान की सहायता के लिए पात्र हैं।

4. खच्चर वालों के लिए सहायता
इस योजना में बैंकों द्वारा उनकी उधार दरो पर ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। 25% की पूंजी इमदाद प्रदान की जायेगी बशर्ते कि वह 10,000 रूपए से अधिक न हो।

इसके अलावा, वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू और कश्मीर के लिए निम्नलिखित पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं:-

क्र0 सं0	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत/जारी की गई राशि (लाख रूपयों में)**
1.	तालमूला गांडेरबल, कश्मीर में खीर भवानी पूजा-स्थल का एकीकृत विकास	107.00
2.	बाबा ऋषि तांगमार्ग (कश्मीर) में पूजा स्थल परिसर का एकीकृत	126.00
3.	मुगल गार्डन (निशात बाग) (कश्मीर) (चरण-1) की मौजूदा विकृत/क्षतिग्रस्त दीवार का पुनर्निर्माण	103.00
4.	एशमुकम पूजा-स्थल, कश्मीर का एकीकृत विकास	61.25
5.	मत्तन, कश्मीर (चरण-1) में पूजा स्थल का एकीकृत विकास	104.00
6.	चंदनवाड़ी से पवित्र मुफा तक अमरनाथजी यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़वों पर यात्रियों के लिए ठहरने के स्थानों का निर्माण	109.00
7.	कटरा कस्बे, जम्मू (चरण-1) में जल-निकास का निर्माण और सुधार	125.00
	जोड	735.25

(घ) राज्य के लिए पर्यटन आगमन आकंडे निम्नानुसार हैं:-

	2001	2002	2003 (जुलाई तक)
स्वदेशी	5246948	4570583	3238515
विदेशी	21298	7821	12660

सरकार का यह मानना है कि इस पैकेज के कार्यान्वयन से पर्यटको की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है।

अवसंरचना परियोजना

अवसंरचना परियोजना

Promotion of Tourism in Jammu and Kashmir

†*107. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased.to state:

(a) whether it is a fact that Prime Minister during his recent visit to Kashmir announced a package to improve and promote tourism industry in the State;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of the outlines of the scheme to implement the said package; and

(d) the number of tourists visiting the State during 2000-01,2001 -02 and 2002-03 and whether Government holds a view that by implementing the package, the number of tourists is likely to go up?

Statement

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAGMOHAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes, Sir, the Prime Minister during his visit to Jammu and Kashmir had announced a comprehensive plan to create at least one lakh employment (including self employment) opportunities in the next two years.

(b) and (c) Based on this announcement, a package for revival of tourism has been prepared (for Kashmir Valley). The package has the following components:

1 **Assistance for House boat owners**

The scheme envisages provision of loans by the Banks at their lending rates and the Department of Tourism, Govt, of India to provide a subsidy so that House boat owners get the loan at a rate of 4% interest.

2. **Assistance for Hotels and Guest Houses**

The scheme envisages provision of loans by the Banks at their lending rates to the registered hotels/Guest Houses classified in the categories of A,B, C and D (as per the State Govt, certification norms) except 5 Star Hotels. The Department of Tourism, Govt, of India to provide a subsidy so that hotel owners/guest house owners get a loan at a rate of 4% interest.

†Original notice of the question was received in Hindi.

3. Assistance for Shikara Owners

All registered Shikara Owners are eligible for assistance of a capital grant of Rs. 20,000 for repairs and upgradalionr of their Shikaras.

4. Assistance tor Ponywalas

The scheme envisages provision of loans by the Banks at their lending rates. A capital subsidy of 25% subject to a ceiling of Rs. 10,000 to oe provided.

In addition, the following tourism infrastructure projects have been sanctioned for Jammu and Kashmir during 2003-2004:

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of Projects Sanctioned/released	Amount
1.	Integrated Development of Khir Bhawani Shrine at Talumula Ganderbal, Kashmir	107.00
2	Integrated Development of Shrine Complex at Baba Rishi, Tangmarg (Kashmir)	126.00
3.	Reconstruction of existing deteriorated/damaged wall of Mughal Garden (Nishat Bagh) (Kashmir) (Phase-I)	103.00
4.	Integrated Development of Aishmuquam Shrine, Kashmir	6125
5.	Integrated Development of Shrine at Mattan, Kashmir (Phase-I)	104.00
6.	Construction of Shelter sheds for Yatries at different Padavs on Amarnathji Yatra Route from Chandanwari to Holy Cave	109.00
7.	Construction and improvement of drainage scheme in Katra Town, Jammu (Phase-I)	125.00
	TOTAL	735.25

(d) The tourist arrival figures for the State are as follows:

	2001	2002	2003(uptoJuly)
Domesti	5246948	4570583	323815
c	21298	7821	12660

The Government is of the view that with the implementation of this package the number of tourists is likely to go up.

श्रीमती माया सिंह : सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं। कि अभी हाल ही मैं प्रधानमंत्री जी ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान कश्मीर में पर्यटन सुविधाओं में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से होने वाली आय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जिन स्कीम्स के लिए पैकेज दिया गया है, क्या उन पर काम शुरू हो गया है?
अगर शुरू हो गया है तो वह किस स्टेज पर है और इसकी प्रोग्रेस क्या है?

श्री जगमोहन : ये स्कीम्स सैंक्शन हो गई है और the main purpose was employment generation. For different categories like for ponywalas, for Shikara Owners, for hotel owners, and for boat owners, different schemes have been floated. Subsidy has been given. Soft loan will be given. Some capital grant will also be given. I have got the details, I can give it, or, I will give it to the hon. Member. Rs. 7 crores have been sanctioned by the Central Government as a component of subsidy. Rs. 2.5 crores have already been released.

श्री सभापति : आपने स्टेटमेंट में ये सब बातें दी हैं ना?
श्री जगमोहन : जी हां, दी हैं।

श्रीमती माया सिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने वहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है या कोई ऐसी केन्द्रीय टीम बनाई है,जो वहां जाए और वहां जो काम ले रहे हैं। उनका सर्वेक्षण करे और उन पर नज़र रखे? पिछली बार डल झील की सफाई के लिए करोड़ों रूपया दिया गया लेकिन उसकी सफाई कहीं नज़र ही नहीं आती है।

SHRI JAGMOHAN: There is a Committee headed by the Secretary, Tourism, J & K which oversees this. This has been recently sanctioned. The monitoring is going on.

SHRI LALIT SURI: Mr. Chairman. Sir, in Jammu and Kashmir, there are a number of Government-owned hotels which have not been revived. Among these, one is the Centaur Hotel and the other one is the ITDC

hotel in Gulmarg. There are a number of private-owned hotels also. My question is: Is there any plan to revive them as soon as possible since the tourism is going to go up in that place?

SHRI JAGMOHAN: Yes; Sir. As far as the question of the revival of the Government hotels is concerned, it is for the State Government to decide, *i.e.*, the State Government of Jammu and Kashmir. So far as the private hotels are concerned, they are entitled to subsidy. Except five-star hotels, all other hotles are entitled to subsidy. A subsidy loan at the rate of four per cent is available, and also up to a particular limit for a particular category for Rs. 50,000 per room, per hotel subject to a maximum of 50 per cent of the hotel room strength.

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केन्द्र

*108. डा. कुमकुम राय : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है,

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी हां, राज्यों में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने की स्कीम है |

(ख) इस स्कीम के शुरु किए जाने से अब तक विभाग ने निम्नलिखित राज्यों में परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध कराई हैं |

1. अरूणाचल प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. जम्मू और कश्मीर
5. केरल